



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

---

शिमला, बोरवार, 30 अक्टूबर, 2003/8 कार्तिक, 1925

---

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 30 अक्टूबर, 2003

संख्या एल० एल० आर०-डी० (6)-15/2002-लेज.—भारत के राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 17-9-2003 को यथा अनुमोदित हिमाचल प्रदेश सड़क अवसंरचना संरक्षण विधेयक, 2002 (2002 का विधेयक संख्यांक 15) को वर्ष 2003 के

अधिनियम संख्यांक 20 के रूप में अनुच्छेद 348(3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,

सचिव

2003 का अधिनियम संख्यांक 20.

## हिमाचल प्रदेश सड़क अवसंरचना संरक्षण अधिनियम, 2002

(भारत के राष्ट्रपति द्वारा तारीख 17-9-2003 को यथा अनुमोदित)

सड़क अवसंरचना के दुरुपयोग, नुकसान, अप्राधिकृत उपयोग और अतिक्रमण के निवारण का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सड़क अवसंरचना संरक्षण अधिनियम, 2002 है ।

संक्षिप्त नाम  
और  
विस्तार ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश पर होगा ।

2. इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

परिभाषाएं ।

(क) “कृषि” के अन्तर्गत उद्यान-कृषि, दुग्ध उद्योग, कुकट पालन उद्योग और किसी फलोद्यान का रोपण और रखरखाव भी है ;

(ख) “अपील प्राधिकारी” से, राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन उसे प्रदत्त किन्हीं या समस्त कृत्यों का पालन करने के लिए नियुक्त, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के परिक्षेत्र का प्रभारी मुख्य अभियन्ता अभिप्रेत है ;

(ग) “भवन” से, कोई गृह, झोंपड़ी, शैड या कोई छत संरचना, जो किसी भी प्रयोजन के लिए या किसी भी प्रकार की सामग्री से निर्मित हो, और उसका प्रत्येक भाग, अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत दीवार या ईंट या पत्थर (मैसनरी) का प्लेटफार्म या ईंट या पत्थर (मैसनरी) की खाई या नाली भी है किन्तु इसके अन्तर्गत टेंट या कृषि प्रयोजन के लिए बनाई चहारदीवारी नहीं है ;

(घ) “भवन रेखांक” से, किसी भी सड़क के या सड़क के किसी भाग के किसी भी ओर का रेखांक अभिप्रेत है जिसे सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी सड़क या उसके किसी भाग की बाबत विहित रीति में नियत किया गया है ;

(ङ) “पुष्टि प्राधिकारी” से, इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन उसे प्रदत्त किन्हीं या समस्त कृत्यों का पालन करने के लिए सरकार द्वारा राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियुक्त, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग का कोई प्राधिकारी, जो कार्यकारी अभियन्ता की पंक्ति से नीचे का न हो, अभिप्रेत है ;

(च) “नियन्त्रित क्षेत्र” से, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए हिमाचल प्रदेश सड़क पार्श्व भूमि नियन्त्रण अधिनियम, 1968 की धारा 3 के अधीन इस रूप में घोषित क्षेत्र अभिप्रेत है ;

(छ) “नियन्त्रित रेखांक” से, किसी भी सड़क या सड़क के किसी भाग के किसी भी ओर का, भवन रेखांक से परे ऐसी सड़क या उसके भाग की बाबत, सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विहित रीति में निहित कोई रेखांक अभिप्रेत है ;

- (ज) "विभाग" से, हिमाचल प्रदेश सरकार का ऐसा विभाग अभिप्रेत है जिसे सड़क अवसंरचना से सम्बन्धित कार्य सौंपा गया हो ;
- (झ) "सरकार" से, हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है ;
- (ञ) "नक्शे" से, इस अधिनियम की धारा 4 के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी मण्डल का सड़क अवसंरचना नक्शा अभिप्रेत है ;
- (ट) "राजपत्र" से, राजपत्र हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है ;
- (ठ) "पूजा स्थल" के अन्तर्गत कोई मन्दिर, गिरजाघर, मस्जिद, इमामबाड़ा, टनकिया, ईदगाह, समाधि, मठ, सती स्थल भी हैं ;
- (ड) "विहित" से, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;
- (ढ) "विहित प्राधिकारी" से, इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन उसे प्रदत्त किन्हीं या समस्त कृत्यों का पालन करने के लिए सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त, कोई प्राधिकारी, जो हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियन्ता की पंक्ति से नीचे का न हो, अभिप्रेत है ;
- (ण) "पुनरीक्षण प्राधिकारी" से, इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन उसे प्रदत्त किन्हीं या समस्त कृत्यों का पालन करने के लिए सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियुक्त, सचिव (लोक निर्माण विभाग), हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है ;
- (त) "सड़क" से, हिमाचल प्रदेश सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित सड़क अभिप्रेत है, और इसके अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्च मार्ग अधिनियम, 1956 के अधीन घोषित राष्ट्रीय उच्च मार्ग भी होंगे ;
- (थ) "सड़क अवसंरचना" से, परिवहन या संचार के लिए सड़क, रास्ते और गलियां अभिप्रेत हैं, और इसके अन्तर्गत हैं,—

1956 का 43

- (i) अर्जित सड़क भूमि चौड़ाई ;
- (ii) सभी प्रकार की सड़कें और उनकी संरचनाएं जैसे कि सड़क खंडजा, सोल्डरज, रिटैनिंग वाल्ज, ब्रैस्ट वाल्ज, टी वाल्ज, आर-पार निकासी, मोड़ (कर्व), सड़क किनारे की नालियां (ड्रेन्ज), सड़क जंक्शनज, मैडियनज, गति अवरोधक, आई सी रम्बल, स्ट्रीप्स, गली में प्रकाश व्यवस्था (स्ट्रीट लाईटिंग), यातायात बलियां इत्यादि ;
- (iii) सड़क परिवहन और संचार प्रणाली की अनुषंगी कोई अन्य संरचना ;
- (iv) पहुंचायक (एपरोचिज), रिटैनिंग वाल्ज, विंग वाल्ज, संरक्षक कार्यों और सम्बद्ध संरचनाओं सहित पुल ;
- (v) इन्टरचेंजिज, ग्रेड सेपरेटज, डिवाइडरज और अन्य अनुषंगी संरचनाओं सहित एक्सप्रेस वेज ;
- (vi) रोड फर्नीचर, जैसे कि पैराफिट्स, रेलिंग, मोड़दार पत्थर (कर्व स्टोन) किलोमीटर स्टोन, बेंच, कैट आईज, रिफ्लेक्टरज, पैडस्टलज और साईन बोर्ड, व्हीकलज और करैस बैरियर ;
- (vii) रोड ओवर ब्रिज, फ्लाई ओवर और निचले पार मार्ग (अन्डर पासिज) और उनसे सम्बद्ध संरचनाएं ;
- (viii) सड़क किनारे का पार्किंग क्षेत्र ;



- (ix) सड़क किनारे पौधरोपण, नर्सरी हैजिज और अन्य लैण्ड स्केप मर्दे ;
- (x) टॉल बूथ/प्लाजा ;
- (xi) सुरंगे और अनुषंगी संरचनाएं ;
- (xii) वे-साईड (सड़क किनारे की) प्रसुविधाएं/संरचनाएं, जैसे कि वर्षा शालिकाएं, ले-वाएज, बस लेन्ज, पब्लिक कन्वेन्यसिज, पार्क और सड़क के साथ मरकारी भूमि पर अवस्थित खुले स्थान ;

(द) “सचिव” से, सचिव (लोक निर्माण विभाग), हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है, और इसके अन्तर्गत इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन सचिव की समस्त या किन्हीं शक्तियों और कृत्यों के प्रयोग और पालन के लिए सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा, तत्समय नियुक्त कोई व्यक्ति भी है ; और

(ध) “कार्य निरीक्षक” से, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग का कोई कर्मचारी अभिप्रेत है, जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा, इस रूप में नियुक्त किया गया हो और उसके अन्तर्गत विभाग का सड़क निरीक्षक और कार्य पर्यवेक्षक भी है ।

### 3. कोई भी व्यक्ति —

- (i) सड़क अवसंरचना के अधीन सरकारी भूमि पर अधिक्रमण नहीं करेगा ;
- (ii) सड़क अवसंरचना पर या से, कोई स्थाई, अस्थायी या जंगम संरचना नहीं बनाएगा ;
- (iii) सड़क अवसंरचना पर पशुधन बांधने सहित कर्मशाला के परिनिर्माण द्वारा और वाणिज्यिक क्रियाकलाप के कार्यान्वयन द्वारा सड़क का दुरुपयोग नहीं करेगा ;
- (iv) सड़क किनारे की निकासी और क्रास निकासी प्रणाली को अवरोध नहीं करेगा/नुकसान नहीं पहुंचाएगा ;
- (v) प्राईवेट सम्पत्तियों से सड़क की ओर मैलापानी/मक (अमेचयवस्तु) नहीं मोड़ेगा ;
- (vi) सड़कों पर उत्खनित मिट्टी/कचरे का ढेर नहीं लगाएगा और सड़क पर अप्राधिकृत रूप से सामग्री का ढेर नहीं लगाएगा ;
- (vii) सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना सड़क अवसंरचना को नहीं खोदेगा/नुकसान नहीं पहुंचाएगा ;
- (viii) अप्राधिकृत रूप से हैंड पम्प और पेट्रोल पम्प स्थापित नहीं करेगा ;
- (ix) पुलों, रोड ओवर ब्रिज, फ्लाईओवर और निचले पार मार्गों (अण्डरपासिज), जिनके अन्तर्गत पहुंचायक मार्ग (एपरोचिज) रिटेनिंग वॉलज और विंग वॉलज, पैराफिटज, रेलिंगज और प्रकाश व्यवस्था (लाईटिंग सिस्टम), संरक्षण कार्य, सुरंगें और उनके अनुषंगी संरचनाएं और अन्य संरचनाएं जैसे कि, सड़क खड्गों, सोल्डरज, रिटेनिंग वॉलज, ब्रैस्ट वॉलज, टौ वॉलज, आर-पार निकासी (क्रास ड्रेनेज) और सड़क के किनारे की नालियां (रोडसाईड ड्रेनेज), सड़क जंकसन्ज, मैडीयन्ज, गति अवरोधक, आई/सी रम्बल सटोपैज, गली में प्रकाश व्यवस्था (लाईटिंग सिस्टम) यातायात बलियां (ट्रैफिक लाइटस), बैरीकेडज, क्रैश बैरियर, साईन बोर्ड, किलोमीटर स्टोनज, रैफरेंस पिलरज, बाऊंडरी पिलरज, सड़क पहचान चिन्ह

सड़क अव-  
संरचना पर  
कतिपय  
कार्यों का  
प्रतिषेध ।

और अवसंरचना, पैंडस्टल, बैंच, टाल बूथ/प्लाजा, वे-साईड (सड़क किनारे की) सुख सुविधाएं जैसे कि वर्षा शालिकाएं, ले-वाईज, बस लेन, पब्लिक कन्वेनियंस, पार्क और सड़क के साथ खुले स्थान और साथ में कोई संरचना, जो कि सड़क परिवहन प्रसुविधाओं और सड़कों के रख-रखाव के लिए हैं, भी सम्मिलित है, को क्षतिग्रस्त/विरूपित नहीं करेगा ;

- (x) सड़क-दुर्घटनाग्रस्त या बेकार या अनुप्रयोज्य स्थानों या माल/मशीनरी को खड़ा नहीं करेगा ;
- (xi) सड़क किनारे की पौधरोपण, नर्सरी, हैजिज और अन्य लैंड स्केप मदों को क्षतिग्रस्त नहीं करेगा/नहीं उखाड़ेगा ;
- (xii) अप्राधिकृत रूप से होडिंग प्रदर्शित नहीं करेगा ;
- (xiii) हिमाचल प्रदेश खुले स्थान (विद्रूपिता निवारण) अधिनियम, 1985 के अधीन प्रतिषिद्ध कोई कार्य नहीं करेगा ;
- (xiv) अप्राधिकृत रूप से स्वागत द्वार और आरचिज इत्यादि का परिनिर्माण नहीं करेगा ;
- (xv) सड़क अवसंरचना के लिए हानिकारक लोप एवं कृत का कोई कार्य नहीं करेगा, जो इस धारा के अधीन अधिसूचित किया जा सकेगा ;
- (xvi) क्षेत्र में खनन के कारण सड़क अवसंरचना क्षतिग्रस्त नहीं करेगा ; और
- (xvii) नियन्त्रित क्षेत्र में किसी संरचना का परिनिर्माण या विनिर्माण नहीं करेगा ।

सड़क अव-  
संरचना  
नक्शा ।

4 (1) सड़क अवसंरचना का प्रभारी कार्यकारी अभियन्ता अपनी अधिकारिता में सड़क अवसंरचना का नक्शा 1:500 के स्केल पर सड़क की लम्बाई और चौड़ाई को दर्शाते हुए, तैयार करेगा ।

(2) नक्शा, भवन और नियन्त्रण रेखाओं तथा सड़क अवसंरचना के साथ-साथ राजस्व विभाग द्वारा सड़क अवसंरचना की पहचान तथा सीमांकन के लिए संदर्भ बिन्दुओं के रूप में नियतभूमि चिन्हों को भी दर्शाएगा और नक्शा सम्बन्धित परिक्षेत्र के प्रभारी मुख्य अभियन्ता द्वारा अनुमोदित किया जाएगा ।

(3) सरकार, सड़कों के नक्शों की, उनकी सीमाओं तथा अन्य महत्वपूर्ण भूमि चिन्हों को दर्शाते हुए, विद्यमानता तथा ऐसे नक्शों की, सड़क अवसंरचना के प्रभारी मुख्य अभियन्ता के कार्यालय में, जन-साधारण के निरीक्षण के लिए उपलब्धता को समाचार पत्रों में प्रकाशन के माध्यम से जन-साधारण को सूचित करेगी और सरकार समाचार पत्रों में इस नोटिस के प्रथम प्रकाशन से 60 दिन के भीतर जन-साधारण से आक्षेप भी आमन्त्रित करेगी और इसी प्रकार उनमें तत्पश्चात् किए गए प्रत्येक परिवर्धन या परिवर्तन के लिए जन-साधारण से आक्षेप आमन्त्रित करेगी ।

(4) किए गए आक्षेपों को न्याय निर्णीत करने के पश्चात्, सरकार ऐसे नक्शों को अन्तिम रूप देगा और उनके सन्दर्भ (रैफरेंस) और उपयोग के लिए कार्यकारी अभियन्ता के कार्यालय में उनकी विद्यमानता और उपलब्धता को वास्तविक जन-साधारण को सूचित करेगी ।

(5) उप-धारा (3) के अधीन कार्रवाई करने के पश्चात् नक्शा, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के मण्डल में, सड़क अवसंरचना का संदर्भ अभिलेख (रैफरेंस रिकार्ड) हो जाएगा और मण्डल के सड़क अवसंरचना नक्शों के रूप में जाना जाएगा ।

1985 क  
12

(6) विहित/पुष्टि प्राधिकारी की अधिकारिता में हुए समस्त प्रतिषिद्ध क्रिया-कलापों को, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के सम्बन्धित मण्डल के इस "सड़क अवसंरचना नक्शे" के संदर्भ में, अवधारित किया जाएगा । ॥

(7) जनता, मण्डल के सड़क अवसंरचना नक्शे का निरीक्षण कर सकेगी तथा क्षेत्र के सम्बन्धित कार्यकारी अभियन्ता से विहित फीस के संदाय पर इसकी अनुप्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर सकेगी ।

(8) उच्च मार्ग के साथ लगती भूमि के नियन्त्रण के लिए और अधिकरणों को हटाने के लिए सरकार राष्ट्रीय उच्च मार्गों के दाईं ओर से परे प्राइवेट भूमि पर भवन रेखांक और नियन्त्रण रेखांक का सीमांकन और प्रवर्तन करेगी ।

5. यह सुनिश्चित करना, यथास्थिति, विहित प्राधिकारी या कार्य निरीक्षक का कर्तव्य होगा कि अधिनियम की धारा 3 के अधीन प्रतिषिद्ध कोई भी क्रिया-कलाप उसकी अधिकारिता के भीतर न हो ।

विहित प्राधिकारी के कर्तव्य ।

6. (1) धारा 3 के अधीन प्रतिषिद्ध क्रिया-कलापों के नियन्त्रण और रोक के लिए आदेश (1) धारा 3 के अधीन प्रतिषिद्ध किसी क्रिया-कलाप के ध्यान में आने पर, विहित प्राधिकारी व्यक्तिक्रमी को, प्रतिषिद्ध क्रिया-कलाप को तत्काल रोकने का निर्देश देते हुए आदेश जारी करेगा और जहां आवश्यक हो, सड़क अवसंरचना की यथापूर्व स्थिति को प्रत्यावर्तित करने के आदेश देगा ।

धारा 3 के अधीन प्रतिषिद्ध क्रिया-कलापों के नियन्त्रण और रोक के लिए आदेश ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन विहित प्राधिकारी के आदेश में लिखित में स्पष्टतया प्रतिषिद्ध क्रिया-कलाप वर्णित रहेगा और नक्शे के सुसंगत भाग पर स्कैच के माध्यम से प्रतिषिद्ध क्रिया-कलाप का अवस्थान (लोकेशन) और ऐसे क्रिया-कलाप का विस्तार और पहले ही कारित या कारित होने वाला नुकसान भी उपदर्शित रहेगा ।

(3) विहित प्राधिकारी, व्यक्तिक्रमी को यह भी निर्देश देगा कि वह नोटिस के जारी होने से 3 दिन के भीतर प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया को शुरू करते हुए सड़क अवसंरचना की प्रास्थिति को इसकी वास्तविक स्थिति में, विनिर्दिष्ट समयावधि में प्रत्यावर्तित करेगा और उसे अनुज्ञात समय के भीतर पूरा करेगा । ॥

(4) विहित प्राधिकारी विनिर्दिष्टतः उपदर्शित करेगा कि इस धारा के अधीन पारित किसी निर्देश या आदेश का अनुपालन करने में असफल रहने की दशा में, अधिरोपित की जाने वाली प्रत्यावर्तन लागत के अतिरिक्त, व्यक्तिक्रमी के जोखिम और लागत पर यथापूर्व स्थिति को बनाए रखने के लिए कदम उठाए जाएंगे । इस प्रकार उपगत व्यय भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किए जाने के लिए दायी होगा और विहित प्राधिकारी सरकार को इसे अधिकृत करेगा और विहित रीति में, प्रतिषिद्ध क्रिया-कलाप के करने में प्रयुक्त तोड़ी गई सम्पत्ति को विक्रीत करेगा ।

(5) नोटिस की तामील सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में यथा उपबन्धित रीति में करवाई जाएगी ।

(6) इस धारा के अधीन पारित कोई भी आदेश किसी भी सिविल न्यायालय में, किसी भी आधार पर चुनौती देने के लिए दायी नहीं होगा ।

सड़क अव-  
संरचना पर  
परित्यक्त  
यानों/  
मशीनरी/  
माल का  
हटाना।

7. इस अधिनियम की धारा 11 में यथा उपबन्धित के सिवाए, विहित प्राधिकारी, सड़क अवसंरचना पर परित्यक्त यानों/मशीनरी/माल को परिवर्द्ध करेगा और इसके हटाए जाने की लागत के अतिरिक्त, उस अवधि के दौरान, जिसमें कि यान/मशीनरी/माल विहित प्राधिकारी की अभिरक्षा में रहता है, 1,000 रुपये प्रतिदिन की दर से शास्ति अधिरोपित करेगा :

परन्तु यह कि, यदि परिवर्द्ध यान/मशीनरी/माल 10 दिन से अधिक की अवधि के लिए विहित प्राधिकारी की अभिरक्षा में रहता है, तो पुष्टि प्राधिकारी, परित्यक्त सम्पत्ति के निपटारे के लिए भारतीय पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 25, 26 और 27 के अधीन कार्रवाई करेगा।

1861 का  
5

विहित  
प्राधिकारी  
द्वारा पारित  
आदेश की  
पुष्टि।

8. व्यथित पक्ष, विहित प्राधिकारी द्वारा जारी आदेश के विरुद्ध आक्षेप, उक्त आदेश की तामील से 3 दिन की अवधि के भीतर, पुष्टि प्राधिकारी को दाखिल कर सकेगा। पुष्टि प्राधिकारी व्यथित पक्ष को, व्यक्तिगत रूप से सुनवाई का अवसर देगा और तत्पश्चात्, 15 दिन की अवधि के भीतर, स्वतः आख्यापक और युक्ति-युक्त आदेश द्वारा, विहित प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करते हुए या उसे अपास्त करते हुए आदेश पारित करेगा।

अपील।

9. (1) पुष्टि प्राधिकारी द्वारा पारित किसी भी आदेश के विरुद्ध कोई अपील तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी, जब तक कि अपील, पुष्टि प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए आदेश से 15 दिन के भीतर दाखिल न की गई हो :

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान के पश्चात् अपील स्वीकार की जा सकेगी यदि अपीलकर्ता, अपील प्राधिकारी का समाधान कर देता है कि उसके पास, उस अवधि के भीतर अपील दाखिल न करने के पर्याप्त कारण हैं :

परन्तु यह और भी कि अपीलार्थी ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील दाखिल करते समय विभाग द्वारा यथा निर्धारित पचास प्रतिशत पूर्वानुमानित प्रत्यावर्तित लागत जमा करवाएगा।

(2) अपील प्राधिकारी, अपील दाखिल करने के 15 दिन के भीतर पुष्टि प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करते हुए या उसे अपास्त करते हुए कोई आदेश पारित करेगा।

अपील  
प्राधिकारी  
द्वारा पारित  
आदेश के  
विरुद्ध  
पुनरीक्षण।

10. (1) धारा 9 के अधीन अपील प्राधिकारी द्वारा अपील में पारित आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की संसूचना के 15 दिन के भीतर राज्य सरकार को, पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकेगा।

(2) पुनरीक्षण प्राधिकारी, अपील प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध दाखिल किए गए पुनरीक्षण आवेदन के 15 दिन के भीतर अपील प्राधिकारी के आदेश की पुष्टि करते हुए या उसे अपास्त करते हुए, कोई आदेश पारित कर सकेगा। सरकार इस धारा के अधीन किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला आदेश, ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का व्यक्ति-युक्त अवसर प्रदान किए बिना, पारित नहीं करेगा।

11. (1) विहित प्राधिकारी किसी भी व्यक्ति को, जो धारा 3 के खण्ड (i), (iii) और (viii) में यथा निर्दिष्ट किसी भी प्रतिषिद्ध क्रिया-कलाप में संलिप्त हो, सड़क की मूल संरचना को उसकी मूल स्थिति में प्रत्यावर्तित करने के आदेश दे सकेगा और यदि ऐसा व्यक्ति, ऐसे आदेश के पारित किए जाने की तारीख से तीन दिन की अवधि के भीतर प्रत्यावर्तन कार्य आरम्भ करने और दिए गए समय के भीतर पूरा करने में असफल रहता है, तो विहित प्राधिकारी व्यक्ति के खर्च पर आदेशों को प्रभावी बनाने के लिए, ऐसी कार्यवाई करेगा, जो उसे आवश्यक प्रतीत हो।

प्रत्यावर्तन लागत और प्रत्यावर्तन फीस का उद्ग्रहण।

(2) यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों या उप-धारा (1) के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करता है या अनुपालन करने में असफल रहता है, तो विहित प्राधिकारी मुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति को, सड़क अवसंरचना के प्रत्यावर्तन की लागत के अतिरिक्त प्रत्यावर्तन फीस के रूप में कोई रकम संदत्त करने का निदेश दे सकेगा, जो,—

- (i) धारा 3 के खण्ड (ii), (iv), (v), (vii), (ix), (xi), (xvi) और (xvii) में यथा निर्दिष्ट किन्हीं प्रतिषिद्ध क्रिया-कलापों के उल्लंघन के लिए प्रत्यावर्तन लागत की पांच गुणा होगी ;
- (ii) धारा 3 के खण्ड (vi) में यथा निर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रिया-कलापों के उल्लंघन के लिए, उत्खनन की गई मिट्टी/मलबे की वाहन प्रति घन मीटर या उसके भाग के लिए प्रतिदिन पांच सौ रुपये की दर से और ढेर लगा कर रखी गई सामग्री (मैटीरियल) की वाहन प्रति ट्रक भार या उसके भाग के लिए प्रतिदिन एक हजार रुपये की दर पर होगी ;
- (iii) धारा 3 के खण्ड (xii) में यथा निर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रिया-कलापों के उल्लंघन के लिए, पांच सौ रुपये प्रति वर्ग मीटर प्रति मन्ताह होगी जब तक कि ऐसा कार्य जारी रहता है ;
- (iv) धारा 3 के खण्ड (xiv) में यथा निर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रिया-कलापों के उल्लंघन के लिए निर्माण के प्रति मीटर (पर रनिंग मीटर) के लिए प्रतिदिन एक हजार रुपये की दर पर होगी ;
- (v) धारा 3 के खण्ड (xiii) या (xv) में यथा निर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रिया-कलापों के उल्लंघन के लिए हटाए जाने की लागत से छः गुणा की दर पर होगी ।

स्पष्टीकरण.—(1) इस धारा के उपबंधों के अधीन देय समस्त प्रत्यावर्तन लागत और फीस, विहित प्राधिकारी के पास सात दिन के भीतर जमा की जा सकेगी, ऐसा न होने पर यह भू-राजस्व के बकाया के रूप में, ब्याज सहित वसूल की जाएगी जो जमा के लिए अनुमत अन्तिम दिन के अगले दिन से आरम्भ होगा।

(2) हटाने/प्रत्यावर्तन की लागत, स्फीति (इन्फ्लेशन) के लिए सम्पूर्ण रूप से अनुक्रमणित हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग की लागत दरों/सिद्धान्तों (प्रिसोपलज) की चालू सूची के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

अपराध ।

12. (1) कोई व्यक्ति, जो धारा 3 के अधीन प्रतिषिद्ध कोई कृत्य करता है या इस अधिनियम की धारा 5 के अधीन समनुदेशित कर्तव्यों का निर्वहन करने में असफल रहता है तो वह दोनों में से किसी भ्रान्ति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

(2) कोई भी न्यायालय, किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध उप-धारा (1) के अधीन दण्डनीय किसी भी अपराध के लिए तब तक संज्ञान नहीं लेगा, जब तक कि सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत लोक सेवक द्वारा लिखित रूप में शिकायत दर्ज नहीं कर दी जाती ।

सड़क अव-  
संरचना की  
बाबत कति-  
पय सुवि-  
धाओं के  
लिए अनुज्ञा ।

13. प्रत्येक व्यक्ति, जो निम्नलिखित सुविधाएं चाहता है, अर्थात् :—

- (i) सड़क अवसंरचना से निजी (प्राइवेट) सम्पत्ति के लिए पहुंच ;
- (ii) सड़क या पुल के साथ-साथ या आर-पार, पाईप लाईन, जल-मल (सीवरेज) लाईन, विद्युत केबल, टेलीफोन केबल इत्यादि सेवाएं बिछाना ;
- (iii) विद्यमान सड़क के दोनों तरफ 50 मीटर तक या पुल के प्रवाह के विरुद्ध या प्रवाह के साथ 500 मीटर तक खुदाई (माईनिंग) क्रिया-कलाप ;
- (iv) अर्जित और नियंत्रित क्षेत्र के साथ कोई निजी या वाणिज्यिक क्रिया-कलाप कार्यान्वित करना ;
- (v) अर्जित और नियंत्रित क्षेत्र के भीतर होडिंग लगाना ;
- (vi) अर्जित और नियंत्रित क्षेत्र के भीतर हैंड पम्प स्थापित करना ;
- (vii) दुर्घटनाग्रस्त यानों/मशीनरी को 48 घण्टों तक सड़क पर खड़ी (पार्क) करना ;
- (viii) सामग्री/माल का सड़क पर 48 घण्टों से अनधिक अवधि के लिए अस्थायी ढेर लगाना ;

इस धारा के उपरोक्त खण्ड (i) से (vi) के अधीन सुविधा की बाबत अपनी अधिकांशता के अधीन सड़क अवसंरचना के प्रभारी कार्यकारी अभियन्ता को तथा खण्ड (vii) और (viii) के अधीन सुविधा की बाबत प्रभारी कनिष्ठ अभियन्ता को, लिखित रूप में अनुज्ञा के लिए आवेदन करेगा । अनुज्ञा के लिए ऐसा प्रत्येक आवेदन विहित रीति में होगा :

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन अन्तर्विष्ट अपेक्षाओं की अनुपालना न करने पर, वह इस अधिनियम की धारा 11 के उपबन्धों के अनुसार लागत/फीस का संदाय करने का दायी होगा :

परन्तु यह और कि इस धारा में अन्तर्विष्ट प्रसुविधाएं विभाग द्वारा हिताधिकारी के लिए डिपॉजिट बर्क के रूप में उपलब्ध करवाई जाएगी ।

1908 का 5

14. इस अधिनियम के अधीन किसी कृत्य का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए पुष्टि प्राधिकारी/विहित प्राधिकारी की, निम्नलिखित मामलों में वाद का विचारण करते समय, वहीं शक्तियां होंगी जैसी कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित है, अर्थात् :—

- (क) किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति के लिए समन करना और उसे हाजिर कराना तथा उसका शपथ पर परीक्षण करना ;
- (ख) दस्तावेजों का प्रकटोत्तरण और उन्हें पेश किए जाने की अपेक्षा करना ; और
- (ग) कोई अन्य मायला जो विहित किया जाए ।

पुष्टि प्राधि-  
कारी/  
विहित  
प्राधिकारी  
की  
शक्तियां ।

15. इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद या अभियोजन विहित प्राधिकारी या इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत विभाग के किसी अन्य अधिकारी, जो विभाग के वरिष्ठ प्राधिकारी के आदेशों या निर्देशों के अधीन कार्यरत है, के विरुद्ध ग्रहण नहीं किया जाएगा ।

इस अधि-  
नियम के  
अधीन विहित  
प्राधिकारी  
द्वारा की गई  
कार्रवाई के  
लिए  
संरक्षण ।

16. किसी भी सिविल न्यायालय को इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले मामलों से सम्बन्धित किसी भी प्रश्न को ग्रहण करने या विनिश्चित करने की अधिकारिता नहीं होगी ।

सिविल  
न्यायालय  
की अधि-  
कारिता का  
वर्जन ।

17. समस्त सड़क अवसंरचना सरकार की ओर से विभाग की अभिरक्षा में समझी जाएगी, जैसे ही यह अस्तित्व में आती है ।

सड़क अव-  
संरचना का  
निहित किया  
जाना ।

18. सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, हिमाचल प्रदेश राज्य के भीतर नगर निगम, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों और विकास प्राधिकरणों के अधिकारियों को, उनकी अधिकारिता के भीतर सड़क अवसंरचना के बारे में, ऐसी शक्तियों और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सशक्त करेगी जो इस अधिनियम के अधीन अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

इस अधि-  
नियम के  
उपबन्धों का  
हिमाचल  
प्रदेश राज्य  
में स्थानीय  
निकायों  
और विकास  
प्राधिकरणों  
को  
विस्तार ।

19. (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी ।

नियम  
बनाने की  
शक्ति ।

(2) विशिष्टतया पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना

ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात् :—

- (क) इस अधिनियम के अधीन दिए जाने के लिए अपेक्षित या प्राधिकृत किसी नोटिस का प्ररूप और रीति जिसमें इसकी तामील की जा सकेगी ;
  - (ख) इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों का संचालन ;
  - (ग) विहित प्राधिकारी के कार्य का वितरण और आबंटन और विहित प्राधिकारी के समक्ष लम्बित किसी भी कार्यवाही को अन्य विहित प्राधिकारी को अन्तरित करना ;
  - (घ) रीति, जिसमें प्रतिषिद्ध क्रिया-कलापों के कृत्यों के परिणामस्वरूप हुए नुकसान (क्षति) को निर्धारित किया जाएगा और सिद्धान्त, जो ऐसे नुकसान (क्षति) के निर्धारण के विचार में लाए जाएंगे ;
  - (ङ) सड़क अवसंरचना को पहुंच के साधनों (मीनज़ आफ़ एसैस) को बिछाए जाने (ले करने) की रीति ;
  - (च) रीति, जिसमें इस अधिनियम के अधीन अनुमति प्रदान की या नामजूर की जा सकेगी और प्रभारित की जाने वाली फीस ; और
  - (छ) कोई अन्य मामला, जिसे विहित किया जा सकेगा ।
3. इस धारा के अधीन बनाए जाने वाले समस्त नियम, पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अध्वधीन होंगे ।
4. इस धारा के अधीन बनाए जाने वाले समस्त नियम, जैसे ही वह बनाए जाएं, विधान सभा के पटल पर रख जाएंगे ।



AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 20 of 2003.

THE HIMACHAL PRADESH ROAD INFRASTRUCTURE  
PROTECTION ACT, 2002

(AS ASSENTED TO BY THE PRESIDENT ON 17-9-2003)

AN

ACT

*to provide for prevention of misuse, damage, unauthorised use and encroachment of the road infrastructure.*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-third Year of the Republic of India, as follows :—

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Road Infrastructure Protection Act, 2002.

Short title  
and extent.

(2) It shall extend to the whole of Himachal Pradesh.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

Definitions.

- (a) "agriculture" includes horticulture, dairy farming, poultry farming and the planting and upkeep of an orchard ;
- (b) "appellate authority" means the Chief Engineer in-charge of the zone of Himachal Pradesh Public Works Department, appointed by the Government, by notification, in the Official Gazette, to perform any or all of the functions as conferred upon him under this Act and the rules made thereunder ;
- (c) "building" means a house, hut, shed, or other roofed structure, for whatever purpose or of whatsoever material constructed and every part thereof, and includes a wall or masonry platform or masonry ditch or drain but does not include a tent or a fence for agricultural purposes ;
- (d) "building line" means a line on either side of any road or part of a road, fixed in the manner prescribed, in respect of such road or part, by the Government, by notification in the Official Gazette ;
- (e) "confirmatory authority" means any authority not below the rank of Executive Engineer of Himachal Pradesh Public Works Department appointed by the Government, by notification, in the Official Gazette, to perform any or all of the functions as conferred upon him under this Act and the rules made thereunder ;
- (f) "controlled area" for the purpose of this Act shall mean an area declared as such under section 3 of the Himachal Pradesh Roadside Land Control Act, 1963;

- (g) "controlled line" means a line on either side of any road or part of a road beyond the building line, fixed in the manner prescribed, in respect of such road or part, by the Government, by notification in the Official Gazette ;
- (h) "department" means the department of the Government of Himachal Pradesh to whom the work relating to road infrastructure has been entrusted ;
- (i) "Government" means the Government of Himachal Pradesh ;
- (j) "map" means the road infrastructure map of a division, notified by the State Government under section 4 of this Act ;
- (k) "Official Gazette" means the Rajpatra, Himachal Pradesh ;
- (l) "place of worship" includes a temple, church, mosque, imambara, tanquia, idgah, smadhi, math, sati ;
- (m) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act ;
- (n) "prescribed authority" means any authority not below the rank of Junior Engineer of Himachal Pradesh Public Works Department, appointed by the Government, by notification, in the Official Gazette, to perform any or all of the functions as conferred upon him under this Act and the rules made thereunder ;
- (o) "revisional authority" means Secretary (Public Works Department) to the Government of Himachal Pradesh, appointed by the Government, by notification, in the Official Gazette, to perform any or all of the functions as conferred upon him under this Act and the rules made thereunder ;
- (p) "road" means a road maintained by the Government of Himachal Pradesh or any local authority and shall include National Highways declared under the National Highway Act, 1956 ;
- (q) "road infrastructure" means the roads, paths and streets for transport or communication and shall include,—
  - (i) acquired road land width ;
  - (ii) all types of road and their structures, such as road pavements, shoulders, retaining walls, breast walls, toe walls, cross-drainage, kerb, road side drains, road junctions, medians, speed breakers, i/c rumble strips, street lighting, traffic lights etc. ;
  - (iii) any structure ancillary to road transport and communication system ;
  - (iv) bridges including approaches, return walls, wing walls, protection works and allied structures ;
  - (v) expressways including interchanges, grade separators, dividers and other ancillary structures ;
  - (vi) road furniture, such as parapets, railings, kerb stones, kilometre stones, benches, cat eyes, reflectors, pedestals and signboards, barricades and crash barriers ;
  - (vii) road over bridges, flyovers and under passes and their allied structures ;
  - (viii) roadside parking area ;

- (ix) roadside plantation, nurseries, hedges and other landscape items ;
- (x) toll booths/plaza ;
- (xi) tunnels and ancillary structures ;
- (xii) wayside amenities/structures, such as rain shelters, lay byes bus lanes, public conveniences, parks and open spaces located on Government land along the road ;

- (r) "Secretary" means Secretary (Public Works Department) to the Government of Himachal Pradesh and includes any person for the time being appointed by the Government, by notification, to exercise and perform all or any of the powers and functions of the Secretary under this Act and the rules made thereunder ; and
- (s) "Work Inspector" means any employee of the Himachal Pradesh Public Works Department, appointed by the State Government by notification, as such, and includes Road Inspector and Work Supervisor of the department.

### 3. No person shall —

Prohibition of certain acts on road infrastructure.

- (i) encroach upon the Government land under road infrastructure ;
- (ii) raise any permanent, temporary or movable structure on or from road infrastructure ;
- (iii) misuse a road by erecting workshop and carrying out commercial activity including tethering of livestock on road infrastructure ;
- (iv) block/ damage road side drainage and cross drainage system ;
- (v) divert sillage/muck from private properties to the road ;
- (vi) stack/throw excavated earth/debris on roads and unauthorisedly stack material on roads ;
- (vii) dig/damage road infrastructure without permission from competent authority ;
- (viii) unauthorisedly instal hand pumps and petrol pumps ;
- (ix) damage/deface bridges, road over bridges, flyovers and underpasses including approaches, return walls and wing wall, parapets, railing and lighting system, protection works, tunnels and their ancillary structures and other structures such as road pavement, shoulders, retaining walls, breast walls toe walls, cross-drainage and roadside drains, road junctions, medians, speed-breakers, i/c rumble strips, street lighting, traffic lights, barricades, crash barriers, signboards, kilometre stones, reference pillars, boundary pillars, road identification marked infrastructure, pedestals, benches, toll booths/plaza, way side amenities such as rain shelters, lay byes, bus lanes, public conveniences parks and open spaces along the road and including any other structure meant for facilitating road transportation and maintenance of roads ;
- (x) park accidented or condemned or unserviceable vehicles or goods/machinery on the road ;

- (xi) damage/uproot roadside plantation, nurseries, hedges and other landscape items ;
- (xii) un-authorisedly display of hoardings ;
- (xiii) commit an act prohibited under the Himachal Pradesh Open Places (Prevention of Disfigurement) Act, 1985 ;
- (xiv) un-authorisedly erect welcome gates arches etc. ;
- (xv) commit any act of omission or commission that may be notified by the Government under this section as injurious to the road infrastructure ;
- (xvi) damage road infrastructure due to mining in the area ; and
- (xvii) erect or construct any structure in the controlled area.

Road in-  
frastructure  
map.

4. (1) Executive Engineer in-charge of the road infrastructure shall prepare on a scale of 1:500 a map of the road infrastructure within his jurisdiction showing therein the length and width of the road.

(2) The map shall also show important landmarks including building and control lines and landmarks fixed by the Revenue Department along the road infrastructure as reference points for identification and demarcation of the road infrastructure and the map shall be approved by the Chief Engineer in-charge of the Zone concerned.

(3) The Government shall, through publication in newspapers, inform the public regarding the existence of maps of the roads showing their boundaries and other important landmarks and the availability of such maps of public inspection in office of the Executive Engineer-in-charge of the road infrastructure and the Government shall also invite public objections within sixty days of first publication of the notice in newspapers and similarly for every addition or change made therein subsequently :

(4) After adjudicating upon the objections raised, the Government shall finalise such maps and inform the public regarding their existence and availability in the Executive Engineer's office for reference and use.

(5) After action under sub-section (3) has been taken, the map shall become the reference record of road infrastructure in the division of the Himachal Pradesh Public Works Department and shall be known as 'road infrastructure map' of a division.

(6) The occurrence of all prohibited activities within the jurisdiction of the prescribed/confirmatory authority may be determined with reference to this road infrastructure map of the concerned division of Himachal Pradesh Public Works Department.

(7) It shall be open to public to inspect the road infrastructure map of a division and obtain certified copies from the Executive Engineer concerned of the area on payment of prescribed fee.

(8) For control of land along highways and for removal of encroachments, the Government shall demarcate and enforce building lines and control lines on the private lands beyond the right way of National Highways.

5. It shall be the duty of the prescribed authority or Work Inspector, as the case may be, to ensure that no activity prohibited under section 3 of the Act occurs within his jurisdiction.

Duties of prescribed authority.

6. (1) On noting the occurrence of any activity prohibited under section 3, the prescribed authority shall issue an order directing the defaulter to stop forthwith the prohibited activity and where necessary, order the restoration of *status quo* of the road infrastructure.

Orders for control and prevention of prohibited activities under section 3.

(2) An order of the prescribed authority under sub-section (1) shall clearly describe in writing the prohibited activity and also indicate by way of sketch, the location of the occurrence of prohibited activity on a relevant portion of the map and the extent of such activity and the damage already caused or being caused.

(3) The prescribed authority shall also direct the defaulter to restore the status of the road infrastructure to its original position within a specified period of time by starting the process of restoration within 3 days from the issue of notice and complete the same within the allowed time.

(4) The prescribed authority shall indicate specifically that in the event of failure to comply with any direction or order passed under this section, steps shall be taken to restore the *status quo* at the risk and cost of the defaulter, in addition to the restoration cost to be imposed. The expenditure so incurred shall be liable to be recovered as arrears of land revenue and the prescribed authority shall confiscate to the Government and sell the dismantled property used in the commission of a prohibited activity in the prescribed manner.

(5) The service of notice shall be effected in the manner as provided in Code of Civil Procedure, 1908.

(6) Any order passed under this section shall not be liable to be challenged in any civil court on any ground whatsoever.

7. Save as provided in section 11 of this Act, the prescribed authority shall impound vehicles/machinery/goods abandoned on road infrastructure and in addition to the cost of removal, impose a penalty @ Rs.1000/- per day for the period during which the vehicles/machinery/goods remain in the custody of the prescribed authority:

Removal of abandoned vehicles/machinery/goods on road infrastructure.

Provided that if an impounded vehicle/machinery/goods remain in the custody of the prescribed authority for a period more than 10 days, the confirmatory authority shall take action under sections 25, 26 and 27 of the Indian Police Act, 1861 for disposal of abandoned property.

8. The aggrieved party may file objections, against the order issued by the prescribed authority, to the confirmatory authority within a period of 3 days from the service of said order and the confirmatory authority shall afford an opportunity to the aggrieved party to be heard in person and thereafter shall pass an order within a period of 15 days confirming or setting aside the order passed by the prescribed authority through a self speaking and reasoned order.

Confirmation of the order passed by the prescribed authority.

Appeal.

9. (1) No appeal shall be entertained against any order passed by the confirmatory authority, unless, the appeal is filed within 15 days from the passing of order by the confirmatory authority :

Provided that an appeal may be admitted after the expiry of the period specified under this section, if the appellant satisfies the appellate authority that he has sufficient cause for not preferring appeal within that period :

Provided further that the appellant while filing the appeal against such order, shall deposit 50% of the anticipated restoration cost as assessed by the department.

(2) The appellate authority shall, within 15 days of the filing of the appeal, pass an order confirming or setting aside the order passed by the confirmatory authority.

Revision  
against  
order passed  
by appel-  
late autho-  
rity.

10. (1) Any person aggrieved by an order passed in appeal by the appellate authority under section 9 may, within 15 days of the communication of such order, make an application to the Government seeking revision.

(2) The revisional authority shall within 15 days of the filing of revision application against the order of the appellate authority pass an order confirming or setting aside the order of the appellate authority. The Government shall not pass an order under this section prejudiced to any person without giving such person a reasonable opportunity of being heard.

Levy of  
restoration  
cost and  
restoration  
fee.

11. (1) The prescribed authority may order any person, who has indulged in a prohibited activity as referred to in clauses (i), (iii) and (viii) of section 3 to restore road infrastructure to its original state and if such person fails to start the restoration work within a period of 3 days from the date of passing of such order and completing it within the time allowed, the prescribed authority shall take such measures as may appear to him to be necessary, to give effect to the orders at the cost of the defaulter.

(2) If a person contravenes or fails to comply with, any provisions of this Act or any order made under sub-section (1), the prescribed authority may, after giving a reasonable opportunity of being heard, direct such person to pay, by way of restoration fee, in addition to the cost of restoration of road infrastructure,—

(i) for contravention of any prohibited activities as referred to in clauses (ii), (iv), (v), (vii), (ix), (xi), (xvi) and (xvii) of section 3, an amount which shall be five times of the restoration cost;

(ii) for contravention of prohibited activities as referred to in clause (vi) of section 3, an amount @ five hundred rupees per cubic metre or part thereof per day in respect of excavated earth/debris and @ one thousand rupees per truck load or part thereof per day in respect of stacked material ;

- (iii) for contravention of prohibited activities as referred to in clause (xii) of section 3, an amount @ five hundred rupees per square metre per week till the time such act continues ;
- (iv) for contravention of the prohibited activities as referred to in clause (xiv) of section 3, an amount @ one hundred rupees per running metre of the erection per day till the time the act continues ; and
- (v) for contravention of the prohibited activities as referred to in clause (xiii) or (xv) of section 3, an amount @ six times the cost of removal.

*Explanation.*—(1) All restoration costs and fees payable under the provisions of this section shall be deposited with the prescribed authority within seven days, failing which it shall be recovered as arrears of land revenue with interest commencing from the day following the last day allowed for deposit.

(2) Cost of removal/restoration shall be determined as per the current schedule of rates/principles of costing of the Himachal Pradesh Public Works Department duly indexed for inflation.

12. (1) Any person who commits any act prohibited under section 3 or fails to perform the duties assigned under section 5 of this Act shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or fine, or with both.

Offence.

(2) No court shall take cognizance of an offence punishable under subsection (1) against any person, unless a complaint in writing is made by public servant authorised by the Government, by notification, in the Official Gazette.

13. Every person who intends to have the following facilities, namely :—

Permission to certain facilities with respect to road infrastructure.

- (i) an approach to private property from the road infrastructure ;
- (ii) laying of services such as pipeline, sewerage line, electrical cables, telephone cables etc. either along or across the road or bridge;
- (iii) mining activities within 50 metres from either side of existing road or 500 metres upstream or downstream of a bridge;
- (iv) carrying out any private or commercial activity within the acquired and controlled area ;
- (v) display of hoardings within the acquired and controlled area;
- (vi) installation of hand pumps within the acquired and controlled area;
- (vii) parking of accidented vehicles/machinery on the road upto 48 hours ; and
- (viii) temporary stacking of materials/goods on the road for a period not exceeding 48 hours,

shall apply for permission in writing to the Executive Engineer-in-charge of the road infrastructure within his jurisdiction in respect of facility under clauses (i) to (vi) above and to the Junior Engineer-in-charge in respect of facility under clauses (vii) and (viii) of this section and every such application for permission shall be in the prescribed manner:

Provided that failure to comply with the requirements as contained under this section, shall be liable to pay cost/fee as per provision of section 11 of this Act :

Provided further that the facilities as contained in this section shall be provided by the department as a deposit work for the beneficiary.

Powers of confirmatory authority/prescribed authority.

14 The confirmatory authority/prescribed authority shall, for the purpose of performing any function under this Act, have the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 when trying a suit in respect of the following matters, namely:—

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of documents; and

(c) any other matter which may be prescribed.

Protection of actions of the prescribed authority under this Act,

15. No suit or prosecution shall be entertained against the prescribed authority or any other officer of the department authorized under this Act acting under the order or directions of superior authority of the department, for anything, which is done by him in good faith or intended to be done under this Act or any rule made thereunder.

Bar of jurisdiction of civil court.

16. No civil court shall have any jurisdiction to entertain or to decide any question relating to matters falling under this Act or the rules made thereunder.

Vesting of road infrastructure.

17. All the road infrastructure shall be deemed to be in the custody of the department on behalf of Government, as soon as it comes into existence.

Extension of the provision of this Act to local bodies and development authorities in the State of Himachal Pradesh.

18. The Government may, by notification, in the Official Gazette, empower officers of Municipal Corporation, Municipalities, Nagar Panchayats and Development Authorities within the State of Himachal Pradesh to exercise such powers and perform such functions, as may be specified in the notification under this Act, in respect of road infrastructure within their jurisdiction.

power to make rules.

19. (1) The State Government may, by notification, in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.



(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

- (a) the form of any notice required or authorized to be given under this Act and the manner in which it may be served;
- (b) the conduct of proceedings under this Act;
- (c) the distribution and allocation of work to prescribed authority and the transfer of any proceeding pending before a prescribed authority to another prescribed authority;
- (d) the manner in which the damage resulting from acts of prohibited activities may be assessed and the principles which may be taken into account in assessing such damages;
- (e) the manner of the laying out of means of access to road infrastructure;
- (f) the manner in which permission under this Act, may be granted or refused and fees to be charged ; and
- (g) any other matter, which may be prescribed.

(3) All rules made under this section shall be subject to the condition of previous publication.

(4) All rules made under this section shall be laid before the Legislative Assembly, as soon as they are framed.

